



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34453

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए सं.- 2301 वर्ष 2026

शेर सिंह और अन्य

....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : आदित्य प्रकाश वर्मा, रंजना वर्मा, शैलेश वर्मा

प्रत्यर्थी(ओं) के अधिवक्ता : सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश वर्मा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. श्री आर.एस. उमराव ने बार में बयान दिया है कि उन्हें सभी निर्देश अच्छे से पता हैं और वे इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं और उनका कोई शपथपत्र दाखिल करने का कोई इरादा नहीं है और रिट याचिका पर अभिलेख में मौजूद प्रपत्र के आधार पर फैसला किया जाएगा। पक्षकारों की सहमति से, इस स्तर पर रिट याचिका पर फैसला किया जा रहा है।
3. रिट याचिकार का वाद यह है कि रिट याचिकार भूतपूर्व आर्मी मैन हैं, जिसका विवरण रिट याचिका के पैरा 9 में दी गई हैं, जो नीचे दिया गया है:-

"9. यहां यह बताना ज़रूरी है कि याचिका सं. 1, 11.02.2002 को आर्मी में भर्ती हुआ था और 31.05.2019 को नायक के पद से सेवानिवृत्त हो गया था; याची सं. 2, 21.02.2002 को आर्मी में भर्ती हुआ था और 30.11.2018 को हवलदार के पद से मुक्त हो गया था। आर्मी में याची की पिछली सेवा के ज़रूरी अभिलेख की प्रति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इस रिट याचिका के साथ फाइल की जा रही हैं और उन्हें अनुलग्नक सं. 4 के तौर पर संलग्न किया गया है।"

4. रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने अक्टूबर, 2018 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड, प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए भर्ती प्रक्रिया के अनुसार सिविल पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयन में भाग लिया था, रिट याचिकाकर्ताओं को आयोजित एक परीक्षा के अनुसार चुना गया था, चयन सूची मार्च, 2020 में प्रकाशित हुई और उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, हालांकि, अब सेना में पूर्ववर्ती कार्य के संदर्भ में उनके वेतन संरक्षण पर इस बहाने विचार नहीं किया जा रहा है कि 23.12.2020 का एक शासनादेश है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के रिट-ए संख्या 10689/2024 (सीता राम शर्मा और 13 अन्य बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य) के एक फैसले की सहायता लेना चाहा है, जिसमें 23.12.2020 के शासनादेश में निर्दिष्ट कट ऑफ तिथि के संबंध में वर्गीकरण को नकार दिया गया उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अब अन्तरा-न्यायालय अपील विशेष अपील संख्या 1233/2025 (यूपी राज्य और 3 अन्य बनाम विनय और 3 अन्य) होने के कारण, राज्य सरकार की अपील खारिज होने के साथ ही मामला कवर हो गया है।

5. श्री आर.एस. उमराव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामला सीता राम शर्मा (पूर्वोक्त) के निर्णय के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष अपीलीय पीठ द्वारा पुष्टि की गई है।

6. मैंने बार में की गई इस बात को सुना है और अभिलेख को पढ़ा है।

7. तथ्य वाद-बिन्दु में नहीं हैं। यह वाद-बिन्दु नहीं है कि रिट याचिकार भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है। सीता राम शर्मा (पूर्वोक्त) में ऐसा लिखा है।-

"1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल की गई ऊपर दी गई रिट याचिका के ज़रिए, यूपी. सिविल पुलिस 2018 में कांस्टेबल जीडी के लिए चुने गए याची, भूतपूर्व सैनिक के तौर पर उनकी अन्तिम वेतन के हिसाब से वेतन संरक्षण न देने के प्रत्यर्थी के भेदभाव वाले रवैये से नाराज़ हैं। सभी याची भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



में चुने गए और नियुक्त किए गए थे और उनका कहना है कि अगर एक ही चयन के परिणाम में, चुने गए लोगों को अलग-अलग समय पर प्रशिक्षण के लिए चार बैच में भेजा जाता है, तो राज्य का पहले बैच के ट्रेनी को वेतन संरक्षण देना और दूसरे ट्रेनी को सिर्फ इस आधार पर मना करना सही नहीं है कि शासनादेश में भूतपूर्व सैनिक को अगली तारीख से वेतन संरक्षण न देने का फैसला किया गया था।

3. यह बताया गया है कि चयन होने के बाद चुने गए अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के उस समय के हालात की वजह से निदेशक पुलिस प्रशिक्षण, यूपी ने 25 जुलाई, 2020 के अपने आदेश के ज़रिए चुने गए अभ्यर्थी को चार बैच में बाँट दिया, जिन्हें अलग-अलग तारीखों पर अलग-अलग समय के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना था। पहले बैच को अगस्त, 2020 में छह महीने के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, दूसरे बैच को मार्च, 2021 में छह महीने के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, तीसरे बैच को अक्टूबर 2021 में छह महीने के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और आखिरी और चौथे बैच को मई, 2022 में छह महीने के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

4. इस न्यायालय में याचीगण का दावा है कि उन्हें दूसरे बैच में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, जो मार्च, 2021 से शुरू हुआ और सितंबर, 2021 तक छह महीने तक चला। जब पहला बैच अपनी प्रशिक्षण पूरी कर रहा था, तो 23 दिसंबर, 2020 के शासनादेश से पहले उनके लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया था, जिस तारीख को शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि चुने गए लोगों, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, को अब कोई वेतन संरक्षण नहीं दिया जाएगा। शासनादेश में आगे कहा गया कि यह तुरंत लागू होगा। शासनादेश का संबंधित पैराग्राफ, जैसा कि पैराग्राफ 22 में है, नीचे दिया गया है:

"उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्योजन किये जाने की दशा में उनके वेतन निर्धारण के संबंध में राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(1) सेना से सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजन होने पर उन्हें उस पद के वेतनमान में ही वेतन ग्राह्य होगा जिस पद पर उनका पुनर्योजन हुआ है। सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद के वेतनमान का संरक्षण नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे पुनर्योजित सैन्य पेंशनर जिनकी पूरी पेंशन वेतन निर्धारण हेतु उपेक्षाणीय (इग्नोर्ड) है, का वेतन पुनर्योजन के पद के वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा।

(3) ऐसे प्रकरण जिनमें वेतन निर्धारण हेतु पूरी पेंशन उपेक्षाणीय (इग्नोर्ड) नहीं है, उनमें पुनर्योजन पर प्रारम्भिक वेतन सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त वेतन के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा, परन्तु-

(1) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान में ऐसा प्रक्रम उपलब्ध नहीं है, तो उक्त प्रक्रम के ठीक नीचे वाले प्रक्रम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ई) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान का अधिकतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित वेतन से कम है, तो पुनर्योजन के पद के वेतनमान के अधिकतम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ईई) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान का न्यूनतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित अन्तिम वेतन से अधिक है, तो वेतन निर्धारण पुनर्योजन के पद के न्यूनतम पर किया जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित होने वाले वेतन में से, सैन्य सेवा से प्राप्त पेंशन का वह भाग जो उपेक्षाणीय (इग्नोर्ड) नहीं है, घटा दिया जायेगा।

(4)

राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित सैन्य पेंशनर उपरोक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त अपनी पूरी पेंशन अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ सहित आहरित करते रहेंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4- उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे अर्थात शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरण इन आदेशों से आच्छादित होंगे। शासनादेश की तिथि के पूर्व राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हो चुके सैन्य पेंशनरों के प्रकरण पुनरुद्घटित नहीं किये जायेंगे।"

5. याचीगण के अधिवक्ता ने दलील दी कि पहले बैच ने जनवरी, 2021 में अपनी प्रशिक्षण पूरी कर ली थी, उसके बाद उन्हें वेतन संरक्षण दिया गया था और उदाहरण के लिए, कुलदीप सिंह, नए चुने गए कांस्टेबल, पीएनओ सं. 202641386, तारीख 24 जनवरी, 2024 का वेतन निर्धारण अभिलेख में लाया गया है। यह दलील दी गई कि पहले बैच को फायदा दिए जाने के बाद, दूसरे, तीसरे और चौथे बैच में चुने गए अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक भी थे, को यह फायदा नहीं दिया गया।

6. ऊपर बताई गई ये बातें रिट याचिका के पैराग्राफ 14 में उठाई गई हैं, जिसमें कई दूसरे कांस्टेबलों का विवरण है जिन्हें अन्तिम वेतन संरक्षण का फायदा मिला था, और वे खुद को भूतपूर्व सैनिक बता रहे थे। पैराग्राफ 14 के जवाब में प्रति शपथपत्र में, पैराग्राफ 16 के हिसाब से, यह कहा गया है:

"रिट याचिका के पैराग्राफ सं. 14 का विवरण इस हद तक माना जाता है कि 11.10.2020 को पुलिस विभाग में कांस्टेबल कुलदीप सिंह पीएनओ सं. 202641386 के नियुक्ति के समय, 26.8.1977 और 18.5.1983 का शासनादेश लागू था, अभी, भूतपूर्व सैनिक को राज्य सरकार की सेवा में फिर से नियुक्त करने का 23.12.2020 का शासनादेश लागू है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि यह आदेश तुरंत लागू होगा, यानी जिन भूतपूर्व सैनिक को शासनादेश जारी होने की तारीख को या उसके बाद राज्य सरकार की सेवा में अपॉइंट किया गया है, वे इस आदेश के तहत आएंगे।"

7. ऊपर बताए गए प्रति शपथपत्र के पैराग्राफ 14 में कही गई बातों को सिर्फ पढ़ने से पता चलता है कि कुलदीप सिंह को पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्हें 11.10.2020 को नियुक्ति दिया गया था, जब 26.8.1977 और 18.5.1983 के शासनादेश लागू थे और इसलिए उन्हें वेतन संरक्षण का यह फायदा दिया गया था। लेकिन, भूतपूर्व सैनिक की पुनः नियुक्ति के संबंध में 23.12.2020 के शासनादेश के लागू होने पर, उन्हें अपनी पिछली जगह के वेतन संरक्षण का हकदार नहीं माना गया और इसलिए मौजूदा याची को ऐसा कोई फायदा नहीं दिया जा सका।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



इस तरह, यह माना जाता है कि याचीगण को सिर्फ इसलिए वेतन संरक्षण नहीं दिया गया क्योंकि उनकी प्रशिक्षण पहले बैच के बाद पूरी हुई थी, जबकि याचीगण भी पहले बैच की तरह ट्रेनी थे जो बाद में कांस्टेबल बन गए। इस तरह सभी नियुक्ति वर्ष 2018 में हुए चयन और भर्ती के आधार पर चुने गए थे और इसलिए उन्होंने वेतन-समानता का दावा किया।

8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने वेतन संरक्षण से इनकार करने वाले शासनादेश के तहत अपनाए गए दृष्टिकोण का बचाव करने की मांग की है, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अनिल प्रसाद 2022 5 एससीसी 461 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक अधिकार का हवाला दिया गया है, जिसमें भूतपूर्व सैनिक को वेतन संरक्षण का फायदा देने से इनकार करने वाले केंद्रीय सरकार के नियमों को सही ठहराया गया था। इसलिए, यह कहा जाता है कि वेतन संरक्षण का फायदा देने से इनकार करने में सरकार की कार्यवाही में कोई कमी नहीं पाई जा सकती है, जिससे इसे गलत या भेदभावपूर्ण या मनमाना माना जा सके। विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने फैसले के पैराग्राफ 4.5 की सहायता लिया है, जो इस तरह है:

"5.4 इसलिए, सरकारी सेवा में प्रत्यर्थी का वेतन निर्धारण सीसीएस आदेश 1986 के पैरा 8 के बिल्कुल मुताबिक था। पैरा 8 में यह नहीं कहा गया है कि सरकारी सेवा में दोबारा नौकरी मिलने पर, सेवानिवृत्त सशत्रु बल के कर्मचारी को उसकी अन्तिम वेतन के बराबर मूल वेतन तय करने का हक होगा। ऐसा मानना सीसीएस आदेश के पैरा 8 का उल्लंघन होगा। इन हालात में, उच्च न्यायालय ने यह देखकर और यह मानकर बहुत बड़ी गलती की है कि सरकारी सेवा में दोबारा नौकरी मिलने पर सेवानिवृत्त सशत्रु बल के कर्मचारी को सशत्रु बल के कर्मचारी के तौर पर अन्तिम वेतन मिलेगी। इसलिए, उच्च न्यायालय का दिया गया आक्षेपित फैसला और आदेश सीसीएस आदेश, 1986 के पैरा 8 के खिलाफ होने की वजह से पोषणीय नहीं है।"

9. संबंधित पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख देखने के बाद, मुझे लगता है कि इस याचिका में शासनादेश में शामिल संबंधित प्रावधान की तुलना में याचिकाकर्ताओं के साथ हो रहे भेदभाव को ज्यादा चुनौती दी गई है, जो पूर्व सेना कर्मियों को सरकारी गैर-रक्षा प्रतिष्ठान में फिर से नौकरी मिलने पर वेतन सुरक्षा का लाभ देने से मना करता है।

10. याची के अधिवक्ता ने मणिलाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 0 एससी 764 के मामले में दिए गए फैसले पर जोर दिया है, और कहा है कि अगर काउंसिलिंग नहीं हुई और उसमें

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



देरी हुई, तो उसी चयन के तहत एक जैसे और एक जैसे रखे गए टीचरों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता था। उन्होंने फैसले के पैराग्राफ 15 पर भरोसा किया है, जो इस तरह है:

"अपीलकर्ता का वाद राकेश गौर (पूर्वोक्त) के वाद जैसा था, जिसने 05.11.2009 को स्वीकृत किया गया था। इस वाद के खास तथ्य पर हमारी साफ राय है कि डिवीजन बेंच ने अंकुल सिंघल (पूर्वोक्त) और राकेश गौर (पूर्वोक्त) के फैसले में दिए गए तर्क को इस वाद के तथ्यों पर लागू करने के बजाय दिनेश चंद्र डामोर (पूर्वोक्त) के वाद को लागू करके गलती की। जैसा कि अंकुल सिंघल (पूर्वोक्त) में कहा गया था, शैक्षणिक सत्र 2009-10 के लिए प्रवेश लेने वाले छात्रों के एक जैसे ग्रुप के बीच आपस में भेदभाव करना गलत होगा। जैसा कि उसमें बताया गया था, ऐसा नहीं हो सकता कि काउंसलिंग के पहले चरण में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स होने पर भी पात्र हों, जबकि काउंसलिंग के बाद के चरण में प्रवेश लेने वाले दूसरे स्टूडेंट्स पात्र न हों। इसी तर्क पर राकेश गौर (पूर्वोक्त) को राहत दी गई थी। राकेश गौर (पूर्वोक्त) का वाद अपीलार्थी के वाद जैसा ही था। क्या "जो साँस हंस के लिए है, वही साँस हंस के लिए भी होना चाहिए।"

11. इस प्रकार इस याचिका में इस न्यायालय द्वारा निर्धारण किए जाने वाले एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या उसी चयन के चयनित उम्मीदवारों को, जब उन्हें पहले प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, दी गई वेतन सुरक्षा उन याचिकाकर्ताओं को अस्वीकार की जा सकती है, जिन्होंने बाद में प्रशिक्षण प्राप्त किया क्योंकि महामारी कोविड-19 के प्रभाव के कारण प्रशिक्षण चार अलग-अलग बैचों में आयोजित किया जा रहा था। प्रत्यर्थियों की ओर से इस बात से कोई इनकार नहीं किया गया है कि सभी याचिकाकर्ता जिन्हें प्रशिक्षण के लिए दूसरे बैच में भेजा गया था और बाद में उसी विज्ञापन के अनुसार उसी चयन के तहत कांस्टेबल (जीडी) यूपी पुलिस के पद के लिए चुना गया था। प्रशिक्षण ऐसे चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के लिए किया जाने वाला आंशिक अभ्यास है और एक बार उम्मीदवार का चयन हो जाने के बाद, अंतिम रूप से प्रकाशित और घोषित चयन सूची में विचार किए जाने के परिणामस्वरूप प्रशिक्षण होता है। इस प्रकार, नियुक्ति के उद्देश्य से प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार को भेजे जाने के लिए चयनित सूची तैयार होने के बाद चयन का कोई और चरण शेष नहीं रहता इसलिए, चुने हुए अभ्यर्थी को नियुक्ति देना प्रक्रिया का हिस्सा है, और इसलिए, न्यायालय के सोचे-समझे विचार में, अगर प्रत्यर्थियों ने प्रशासनिक पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी तरफ से प्रशिक्षु को अलग-अलग क्लस्टर और ग्रुप में बांटने

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



का फैसला किया, ताकि उन्हें प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग तारीखों पर भेजा जा सके और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी होने पर ऐसे प्रशिक्षु को नियुक्ति दिया जा रहा हो, तो उनके साथ सेवा लाभ, जैसे वेतनमान, भत्ते और दूसरे लाभ के मामले में भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, जो उस पद के लिए मान्य हैं। वरिष्ठता के मामले में भी, चयन सूची को ही फॉलो किया जाना है। मणिलाल (पूर्वोक्त) के मामले में जो निर्णय दिया गया है, वह याचीगण के मामले को पूरी तरह से आच्छादित करता है। न्यायालय ने उसमें माना था कि एक जैसे ग्रुप के बीच भेदभाव को मंजूरी नहीं दी जा सकती। इस तरह, एक ही चयन के तहत चुने गए सभी लोग एक जैसा ग्रुप बनाएंगे और उनका नियुक्ति सिर्फ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का परिणाम होगा, बशर्ते उन्हें प्रशिक्षण के दौरान अस्वीकार कर दिया जाए। एक बार जब एक जैसे ग्रुप को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है, तो सभी सदस्य के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए।

12. प्रशिक्षण के लिए भेजे जा रहे क्लस्टर या ग्रुप्स के आधार पर कोई भी विभेदीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ होगा क्योंकि यह एक जैसे कर्मचारियों को फायदा देने के मकसद से सही विभेदीकरण नहीं होगा। बराबरी का एक तय नियम यह है कि अलग-अलग लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता और एक जैसे लोगों के साथ वेतन में बराबरी और सेवा लाभ के लिए एक जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए।

13. फिरंगी प्रसाद बनाम उ. प्र. राज्य और अन्य (2011) 2 यूपीएलबीईसी 987 के मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि नियुक्ति पत्र जारी करने में नियुक्ति प्राधिकारी की गलती के लिए, याचीगण को नुकसान की स्थिति में नहीं डाला जा सकता। हालांकि यह मामला नियमितीकरण से जुड़ा था, लेकिन चूंकि प्रबंधक ने नियुक्ति आदेश देरी से जारी किए थे और नियमितीकरण नियमों की कट ऑफ तिथि के बाद भी, इसलिए सभी को नियमितीकरण का फायदा देने के लिए एक जैसा माना गया। इस फैसले को आगे महेश नारायण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (रिट ए सं. 55606/2008) के मामले में भी पालन किया गया, जिस पर 19.12.2019 को फैसला हुआ, जिसमें एक विज्ञापन के सभी आवेदक को चुने जाने पर पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा देने के लिए एक होमोजेनियस ग्रुप बना दिया गया था, क्योंकि विज्ञापन और चयन पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म करने से पहले हुए थे, भले ही नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए गए हों।

14. इस मामले को देखते हुए, मुझे शासनादेश में कुछ भी भेदभाव वाला नहीं लगता, जहाँ तक भूतपूर्व सैनिक के लोगों को वेतन संरक्षण न देने की बात है, लेकिन शासनादेश सिर्फ उन मामलों

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में लागू होगा जहाँ अभ्यर्थी इसके जारी होने के बाद चुने गए थे। जिन सभी को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है और जिन्हें आखिर में नियुक्ति दिया जाएगा, वे सभी एक जैसे ग्रुप में होंगे और उन्हें वेतन संरक्षण समेत सभी फायदे मिलेंगे और शासनादेश से उनके दावे पर अभी कोई असर नहीं पड़ेगा।

15. जहां तक विद्वान अधिवक्ता के दिए गए फैसले का सवाल है, मुझे उसमें दिए गए कानून के बारे में कोई झगड़ा नहीं लगता, क्योंकि मेरा भी मानना है कि इस मामले के खास हालात में शासनादेश को रद्द करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह मौजूदा मामले पर लागू नहीं होता है।

16. ऊपर दी गई बातों को देखते हुए, रिट याचिका सफल होती है और उसे मंजूरी दी जाती है। प्रत्यर्थी सं. 3 को निर्देश दिया जाता है कि वे याचीगण को अन्तिम वेतन संरक्षण का लाभ सरेंडर करें, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के तहत प्रशिक्षु के पहले बैच को दिया गया है। सही आदेश पास किया जाएगा और इस आदेश की प्रामाणिक प्रति पेश करने की तारीख से ज्यादा से ज्यादा तीस दिनों के अंदर याचीगण को परिणामी लाभ दिए जाएंगे।

8. इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य बनाम विनय और 3 अन्य (पूर्वोक्त) में निम्नलिखित पढ़ा गया।-

"1. सभी अपीलों में अपील करने वालों की ओर से श्री मनीष गोयल, विद्वान अपर महाअधिवक्ता जिनकी मदद श्री तेज भानु पांडे, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने की, और प्रत्यर्थियों की ओर से उनकी संबंधित अपीलों में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री आर.के. ओझा, जिनकी मदद श्री सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी और श्री आदित्य प्रकाश वर्मा, विद्वान अधिवक्ताओं ने की, को सुना।

2. ये सभी अपीलें 09.04.2025 को एकल न्यायाधीश के एक ही निर्णय और आदेश के खिलाफ पेश की गई हैं, जो रिट ए सं. 10689/2024, सीता राम शर्मा और 13 अन्य बनाम उ. प्र. राज्य और 3 अन्य के साथ जुड़ी हुई रिट याचिका में पारित हुए थे, जिसके तहत यहाँ प्रत्यर्थियों द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका को मंजूरी दी गई थी और अपीलार्थी सं. 3 (यहाँ) को निर्देश दिया गया था कि वे उसमें याचीगण को अन्तिम वेतन संरक्षण का लाभ सरेंडर करें, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के अनुसार प्रशिक्षु के पहले बैच को दिया गया है और उचित आदेश पास किया जाएगा और उक्त आदेश की प्रामाणित प्रति पेश करने की तारीख से ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों का परिणामी लाभ दिया जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. अपीलकर्ता उत्तर प्रदेश राज्य ने इन सभी अपीलों में एक जैसा वाद-बिन्दु उठाया है, और इसलिए, उन पर एक साथ सुनवाई हुई और इस एक ही आदेश से फैसला किया जा रहा है। सभी अपीलों में मुख्य सवाल यह है कि क्या एक ही चुनी गई सूची में रखे गए अभ्यर्थी को उनके नियुक्ति पत्र की तारीख और उनकी प्रशिक्षण की बताई गई तारीख के आधार पर अलग-अलग क्लास का माना जा सकता है। हर अपील में अभ्यर्थी के बारे में असल जानकारी, जैसे कि उनकी पिछली सेवा की जानकारी, नियुक्ति पत्र की तारीख और पत्र में उनके प्रशिक्षण अवधि की बताई गई तारीख, अलग-अलग हो सकती है।

4. आसानी के लिए, असल जानकारी विशेष अपील सं. 1240/2025 से ली जा रही है, क्योंकि वही 09.04.2025 को दिए गए एकल-न्यायाधीश के फैसले और आदेश में मुख्य याचिका थी, लेकिन, मौजूदा एक ही आदेश का परिणाम सभी जुड़े हुए मामलों पर लागू होगा। असल में फर्क सिर्फ जुड़ी हुई अपीलों में जवाब देने वालों/उम्मीदवारों की संख्या का है।

5. विशेष अपील मामलों के इस कंसोलिडेटेड ग्रुप के अभिलेख देखने के बाद, ऐसा लगता है कि इसमें सभी प्रत्यर्थी भारतीय सेना के पुराने सदस्य हैं, जो अलग-अलग समय पर अलग-अलग रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। यह भी लगता है कि हर प्रत्यर्थी को अपनी सेवा का समय पूरा होने पर छुट्टी दे दी गई या सेवानिवृत्त कर दिया गया। उनकी सेवा के अलग-अलग समय में अंतर के बावजूद, इन मामलों में एक आम बात यह सामने आती है कि सभी प्रत्यर्थी ने अपनी मिलिट्री सेवा पूरी कर ली थी और सही प्रक्रिया को फॉलो करके चुने गए थे और उसी चयन सूची में अपनी जगह पक्की की थी, जो अपील के इन बैच का विषय है।

6. राज्य की ओर से पेश हुए अपर महाअधिवक्ता ने कहा कि अक्टूबर 2018 की निदेशक भर्ती के तहत तैयार की गई चयन सूची से नियुक्ति का प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ, क्योंकि प्रशिक्षण इस प्रक्रिया का एक ज़रूरी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगी पाबंदियों की वजह से, राज्य के लिए चुने गए अभ्यर्थी की प्रशिक्षण फेज़ में करना ज़रूरी हो गया था, और इसलिए, अभ्यर्थी के प्रशिक्षण फेज़ के हिसाब से अलग-अलग तारीखों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए। यह भी कहा गया है कि निदेशक, यूपी पुलिस प्रशिक्षण ने 25.07.2020 के अपने आदेश से, चुने गए अभ्यर्थी को अलग-अलग तारीखों और अलग-अलग समय के लिए प्रशिक्षण के लिए चार बैच में बांटा। इसके बाद, पहले बैच ने अगस्त 2020 में छह महीने के लिए प्रशिक्षण शुरू की।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दूसरे बैच ने मार्च 2021 में छह महीने के लिए प्रशिक्षण शुरू की। तीसरे बैच ने अक्टूबर 2021 में छह महीने के लिए और चौथे बैच ने मई 2022 में छह महीने के लिए प्रशिक्षण शुरू की।

7. विद्वान अपर महाअधिवक्ता के अनुसार, राज्य को अलग-अलग बैच में, अलग-अलग समय पर प्रशिक्षण के लिए जाने वाले अभ्यर्थी के लिए अलग-अलग वेतन-संरचना तय करने का पूरा अधिकार था, और अपील करने वाली राज्य ने दूसरे बैच के अभ्यर्थी को वही वेतन संरक्षण दिए बिना नियुक्ति पत्र देना भी सही ठहराया, जो पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए गए सदस्यों को दिया गया था। यह भी कहा गया है कि चयन सूची को सभी उद्देश्यों के लिए एक जैसा वर्ग नहीं माना जा सकता, और राज्य का बाद के तीन बैचों को पहले बैच से अलग रखना सही है, जिन्होंने दूसरे बैचों से पहले प्रशिक्षण पूरी कर ली थी।

8. यह बात पक्की है कि पहले बैच, जिसने जनवरी 2021 में अपनी प्रशिक्षण पूरी की थी, को वेतन संरक्षण का फायदा दिया गया था। विद्वान अपर महाअधिवक्ता की मुख्य दलील यह है कि एक ही सूची से चुने गए अलग-अलग बैच के अभ्यर्थी के साथ किया जाने वाला अलग बर्ताव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत आता है, और इसलिए राज्य को उन चार बैचों के लिए अलग-अलग वेतन-संरचना तय करने का हक है, जिन्होंने अलग-अलग समय पर प्रशिक्षण शुरू की थी।

9. अपनी बात के समर्थन में, विद्वान अपर महाअधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी और प्रधान आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 के नियम 19 का हवाला दिया है, जिसे आसानी से देखने के लिए नीचे दिया गया है:

नियम - 19. प्रशिक्षण

(1) (a) नियम 15 और 16 के तहत कांस्टेबल के पदों पर फाइनली चुने गए अभ्यर्थी को विभाग के प्रमुख द्वारा तय प्रशिक्षण पास करनी होगी। बेसिक प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थी पर पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज मैनुअल के प्रावधान लागू होंगे। अगर बेसिक प्रशिक्षण के लिए अन्तिम रूप चुना गया अभ्यर्थी तय समय सीमा के अंदर प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(b) बेसिक प्रशिक्षण में फेल होने वाले अभ्यर्थी का पुनः परीक्षा पूरक प्रशिक्षण करने के बाद विभाग के हेड द्वारा आयोजन किया जाएगा। पूरक प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण की परीक्षा में फेल होने वाले अभ्यर्थी की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) नियम 17 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा।

10. विद्वान अपर महाअधिवक्ता का कहना है कि कांस्टेबल की पोस्ट पर अन्तिम रूप से चुने गए अभ्यर्थी को विभाग प्रमुख द्वारा बताई गई बेसिक प्रशिक्षण से गुजरना और उसे पास करना ज़रूरी है, ऐसा न करने पर उनका चयन कैंसिल किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि यह नियम अधिकारियों को पूरक प्रशिक्षण और पुनः-परीक्षा कराने और उसके बाद भी फेल होने वाले अभ्यर्थी की सेवा खत्म करने का भी अधिकार देता है, जबकि प्रमोशन से नियुक्त हुए अभ्यर्थी को भी बताई गई प्रशिक्षण पूरी करनी होती है और इसलिए, जब तक प्रशिक्षण पूरी नहीं हो जाती, राज्य वेतन संरचना में बदलाव करने के लिए आज़ाद है क्योंकि चयन प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है।

11. इसके उलट, प्रत्यर्थियों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता का कहना है कि राज्य का यह कदम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिले बराबरी के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्यर्थियों को सिविल पुलिस और पीएससी में कांस्टेबल के पदों के लिए 2018 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया के तहत चुना गया था और मार्च 2020 में घोषित नतीजे में उन्हें भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में रखा गया था। उन्होंने आगे कहा कि 23.12.2020 का शासनादेश, जिसमें यह कहा गया है कि उस तारीख के बाद की गई सभी नियुक्तियों को वेतन संरक्षण नहीं मिलेगा, मंज़ूर नहीं है, क्योंकि यह कानून के तय सिद्धांतों के खिलाफ है, खासकर तब जब सभी उम्मीदवारों को एक ही चयन सूची में रखा गया हो। यह भी कहा गया है कि पहले फेज़ में नियुक्त उम्मीदवारों को वेतन संरक्षण का फायदा दिया गया था, जिसे राज्य सरकार ने लगातार माना है।

12. प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता ने आगे मणिलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, एआईआर 2024 एससी 4404 पर की सहायता लिया और कहा कि एक ही चयन के तहत चुने गए सभी अभ्यर्थी एक ही होमोजेनस ग्रुप बनाएंगे और इस होमोजेनस ग्रुप के बीच भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उन्होंने महेश नारायण और अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी और अन्य, रिट ए सं. 55606 ऑफ 2008 पर भी सहायता लिया, जिस पर 19.12.2019 को इस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। ऊपर दिए गए फैसलों पर भरोसा करते हुए, अधिवक्ता का कहना

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है कि इस तरह के अलग बर्ताव को केवल कुछ समझने लायक अंतरों पर ही सही ठहराया जा सकता है, जो इन मामलों के तथ्य में मौजूद नहीं हैं।

13. प्रत्यर्थियों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने प्रशिक्षण के बारे में अपर महाअधिवक्ता की दलील का भी जवाब दिया, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल नियमावली, 2015 का नियम 19। उनके मुताबिक, एकल न्यायाधीश ने सही कहा है कि प्रशिक्षण चुने हुए अभ्यर्थी के लिए एक प्रक्रिया है और एक बार चयन सूची तैयार हो जाने के बाद, अभ्यर्थी को नियुक्ति के मकसद से प्रशिक्षण के लिए भेजने के लिए चयन का कोई और स्तर बाकी नहीं रहता। वह आगे यूपी पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल नियमावली, 2015 के नियम 18 पर भरोसा करते हैं, जिसे आसानी से देखने के लिए नीचे दिया गया है:

नियम - 18. नियुक्ति

(1) नियम 15 और 16 के प्रावधान के तहत, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी के नाम उसी आदेश में लेकर नियुक्ति करेगी, जिस आदेश में वे नियम 15 के क्लॉज़ (g) के तहत तैयार सूची में हैं। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र इस निर्देश के साथ जारी करेगी कि वे पत्र जारी होने की तारीख से एक महीने के अंदर या नियुक्ति पत्र में इस उद्देश्य के लिए बताई गई किसी भी तारीख तक सेवा/प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करें। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसका चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाएगा:

बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो इन नियमों के लागू होने से पहले सेवा में किसी पद पर नियुक्त हुआ हो और उस पद पर काम कर रहा हो, उसे इन नियमों के तहत असल में नियुक्त माना जाएगा।

(2) यदि नियम 17 के अन्तर्गत किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें चयन में अवधारित वरिष्ठता क्रम में अथवा, जैसा भी मामला हो, उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया जाएगा :

बशर्ते कि इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उस पद पर कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त माना जाएगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति इन नियमों के अधीन की गई मानी जाएगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. ऊपर बताए गए नियम पर सहायता से, प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता ने कहा कि नियम 18, नियम 15 और 16 के तहत चुने गए अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी करने के बारे में सोचता है, और उसके बाद ही नियम 19 ऐसे अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने की ज़रूरत बताता है। प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता ने कहा कि नियम का स्कीम साफ़ तौर पर दिखाता है कि नियुक्ति पत्र प्रशिक्षण से पहले दिया जाता है, और इसलिए, प्रशिक्षण को चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जा सकता, जैसा कि एकल न्यायाधीश ने सही कहा है, क्योंकि प्रशिक्षण नियुक्ति के बाद होनी है।

15. हमने अपील करने वालों/राज्य के अधिवक्ताओं के साथ-साथ जवाब देने वालों के अधिवक्ताओं को भी सुना है और अभिलेख को देखा है, जिसमें एकल न्यायाधीश के अभिलेख किए गए नतीजे भी शामिल हैं। कुछ बुनियादी बातें विवाद में नहीं हैं। सभी अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी बैच में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए हों, अक्टूबर 2018 में जारी एक ही भर्ती विज्ञापन के तहत चुने गए थे। चयन सूची एक जैसी थी, चयन प्रक्रिया एक जैसा था, और नियुक्ति एक ही भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए थे।

16. अभिलेख को आसानी से देखने पर ऐसा लगता है कि सभी नियुक्ति पत्र अक्टूबर 2018 की एक ही सीधी भर्ती के तहत किए गए नियुक्ति से जुड़े हैं, जो एक ही विज्ञापन और चयन प्रक्रिया से शुरू हुए थे। किसी भी पार्टी का यह भी मामला नहीं है कि जिस विज्ञापन की वजह से चयन सूची बनी, उसमें ऐसा कोई विभेदीकरण या श्रेणीवार फर्क बताया गया हो। इसके अलावा, राज्य ने यह नहीं दिखाया है कि प्रशिक्षण के लिए चार अलग-अलग फेज में भेजे जाने वाले अभ्यर्थी को किसी सही विभेदीकरण के लिए रखा गया था।

17. ऊपर बताई गई चर्चा को देखते हुए, हमारा मानना है कि अलग-अलग फेज में प्रशिक्षण सिर्फ अपील करने वाली सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतों और कोविड-19 महामारी से पैदा हुई मुश्किलों की वजह से ज़रूरी थी, न कि चयन सूची में शामिल अभ्यर्थी के बीच किसी साफ़ फर्क की वजह से। इसलिए, बाद के बैच में प्रशिक्षण के लिए रखे गए अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से दूर रखना पूरी तरह से मनमाना है और इसमें गलत भेदभाव किया जाता है।

18. विद्वान अपर महाअधिवक्ता की दलील का पूरा आधार यह है कि फेज्ड प्रशिक्षण ने ही चार अलग-अलग श्रेणी बनाई, जिससे राज्य को बाद के बैच का हिस्सा बनने वाले प्रत्यर्थियों से वेतन संरक्षण रोकने के लिए अलग-अलग वेतन-संरचना तय करने में मदद मिली।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



19. हालांकि यह न्यायालय महामारी से जुड़ी ज़रूरतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाओं को मानता है, लेकिन ऐसी बाहरी और कुछ समय की प्रशासनिक मजबूरियां एक ही वर्ग के उम्मीदवारों के बीच अलग बर्ताव को सही नहीं ठहरा सकतीं। अनुच्छेद 14 के तहत मंजूर विभेदीकरण को कंट्रोल करने वाली कानूनी स्थिति इतनी अच्छी तरह से तय है कि उसे और समझाने की ज़रूरत नहीं है और जब तय पैरामीटर पर टेस्ट किया जाता है, तो अपील करने वाले राज्य की तरफ से दी गई वजह जांच में कायम नहीं रह सकती है।

20. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) 1 एससीसी 1 में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि विभेदीकरण साफ़ नहीं होना चाहिए, पक्का नहीं होना चाहिए या समझ से बाहर नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के मुताबिक बराबरी का परीक्षा पास करने के लिए, विभेदीकरण एक समझने लायक अंतर पर आधारित होना चाहिए क्योंकि अनुच्छेद 14 का मकसद हर व्यक्ति को मनमाने भेदभाव से बचाना है, चाहे वह किसी कानून की साफ़ शर्तों की वजह से हो या किसी कानून के गलत इस्तेमाल की वजह से। कोई भी विभेदीकरण एक समझने लायक अंतर पर आधारित होना चाहिए जिसका मकसद हासिल करने के साथ एक लॉजिकल रिश्ता हो, ऐसा न होने पर, ऐसे विभेदीकरण से गलत भेदभाव होता है।

21. सीधी भर्ती समूह- II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1990) 2 एससीसी 715 में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक ही भर्ती विज्ञापन और चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाले अभ्यर्थी सेवा लाभ के लिए एक ही क्लास बनाते हैं। वरिष्ठता तय करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार जब कोई व्यक्ति नियम के अनुसार किसी पोस्ट पर नियुक्त हो जाता है, तो उसकी वरिष्ठता उसकी नियुक्ति की तारीख से गिनी जानी चाहिए, न कि उसके स्थायीकरण की तारीख से। इस प्रिंसिपल को लागू करते हुए, प्रशिक्षण पूरी होने को एक ही चयन सूची में रखे गए अभ्यर्थी के बीच सब-क्लास बनाने के लिए एक बिन्दु नहीं माना जा सकता है।

22. अपील करने वालों ने किसी ऐसे कानूनी नियम की ओर इशारा नहीं किया है जो राज्य को पे फिक्सेशन या वेतन संरक्षण के मकसद से चयन सूची में सब-श्रेणी बनाने का अधिकार देता हो। असल में, राज्य का अपना रुख यह है कि प्रशिक्षण के लिए फेज में भेजना सिर्फ प्रशासनिक ज़रूरत की वजह से मजबूरी में किया गया था। प्रशासनिक ज़रूरत, भले ही वह सही हो, उसे अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक रूप से मंजूर अंतर तक नहीं बढ़ाया जा सकता। इस तरह की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इजाजत देने से राज्य को मनमाने या अचानक हालात के आधार पर एक जैसे हकों को बांटने का मौका मिलेगा, इस प्रथा को सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार गलत बताया है।

23. इसलिए, विद्वान एकल-न्यायाधीश का यह मानना सही था कि प्रत्यर्थी और इसी तरह की स्थिति वाले दूसरे अभ्यर्थी, जिन्हें अक्टूबर 2018 के उसी भर्ती प्रक्रिया से चुना गया था, उन्हें प्रशिक्षण के लिए पहले भेजे गए अभ्यर्थी के पहले बैच को दिए गए वेतन संरक्षण और सेवा लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। संवैधानिक मानक को खुद से लागू करने पर, हमें विद्वान एकल-न्यायाधीश के अभिलेख किए गए निष्कर्ष में कोई कमी नहीं दिखती है।

24. ऊपर बताए गए कारणों से, हमारा मानना है कि अपील करने वाले राज्य ने एक ही चयन सूची में रखे गए उम्मीदवारों के बीच, सिर्फ प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने की तारीखों के आधार पर जो भेदभाव किया है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और गलत विभेदीकरण है।

25. राज्य द्वारा पहले बैच को दिए गए वेतन संरक्षण और उससे जुड़े वेतन-संरचना का फायदा, दूसरे, तीसरे और चौथे बैच के उन अभ्यर्थी से नहीं रोका जा सकता जो उसी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा थे और उसी चयन सूची में रखे गए थे।

26. इसलिए, हमें विद्वान एकल-न्यायाधीश के फैसले में दखल देने का कोई आधार नहीं मिला। इसलिए स्पेशल अपील का बैच फेल हो जाता है और खारिज किया जाता है। विद्वान एकल-न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थी और इसी तरह के सभी दूसरे अभ्यर्थी को वेतन संरक्षण और परिणामी लाभ देने का दिया गया निर्देश पुष्ट किया जाता है। राज्य इस आदेश की तारीख से बारह हफ्तों के अंदर इसका पालन पक्का करेगा। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं।

27. यदि कोई आवेदन लंबित है तो उसका निपटारा हो जाएगा।

9. तदनुसार, रिट याचिका पर सीता राम शर्मा और 13 अन्य (पूर्वोक्त) और उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य बनाम विनय और 3 अन्य (पूर्वोक्त) में दिए गए फैसले के अनुसार फैसला किया जा रहा है।

10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

17 फरवरी, 2026

आशु

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”